POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 02

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 फरवरी, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें देश-प्रदेश के सर्वांगीण विकास और आमजन की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बहुत सी नीतियां बनाती हैं। उन नीतियों के तहत अनेक योजनाएं भी बनती हैं।

लेकिन निचले स्तर तक पहुंचने और उनके क्रियान्वयन में या तो बहुत देरी हो जाती है या उनका लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच ही नहीं पाता। कई योजनाओं में अपात्र लोग भी गैरवाजिब फायदा उठा लेते हैं। इस शिथिलता को दूर करने के लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक माना गया है। यह एक सतत् प्रक्रिया है और सभी सरकारें हमेशा इसे सुनिश्चित करने की कवायद में भी लगी रहती हैं।

हाल ही राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे 'सुशासन के लिए नवाचार' श्रृंखला के तहत जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की पहल पर उदयपुर में शुरू किए गए 'मिशन कोटड़ा' की सफलता सराहनीय है, जो कि कोटड़ा, लसाड़िया, झाड़ोल और फलासिया ब्लॉक्स में संचालित किया गया है। इसी तर्ज पर नीति आयोग द्वारा विकास मानकों को बढ़ावा देने के लिए 'एस्पीरेशन ब्लॉक' प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में प्रारंभ किया है।

इसके माध्यम से देश में सबसे पिछड़े ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संबंधित ब्लॉक्स के स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे में प्रगति के लिए प्रयास होंगे और लगातार मॉनिटरिंग करते हुए लोकहितकारी विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा इसके लिए उदयपुर जिले का खेरवाड़ा ब्लॉक चयनित है।

अकसर नौकरशाही यानी प्रशासनिक तंत्र की कई बार कमियां उजागर होती रहती हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशासनिक तंत्र को दक्षतापूर्ण, प्रभावी, उत्तरदायी और ईमानदार होना चाहिए। साथ ही उनमें जन कल्याण की भावना भी विकसित हो, तभी सुशासन कहा जा सकता है।

यह अच्छा संकेत है। हमारी सरकारों का फोकस ऐसे कार्यबल को तैयार करने में लगा है, जिनमें राज्य और केंद्र सरकारों को समन्वय से काम करने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार कानून: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनाया अहम फैसला

लोक सेवकों के रिश्वत लेने के मामले में प्रत्यक्ष सबूत नहीं होने पर परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर सजा हो सकती है। मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता के प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध नहीं होने पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है।

पांच जजों की संविधान पीठ ने एक मामले पर सुनवाई के बाद यह अहम फैसला सुनाया है। पीठ में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर.गवई, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, जस्टिस बी.वी. नागरत्न व जस्टिस ए.एस. बोपन्ना शामिल है।

संविधान पीठ की 3 अहम टिप्पणियां

1. *संविधान पीठ ने कहा कि अदालतों को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ नरमी नहीं बरतनी चाहिए।*
2. *भ्रष्ट अधिकारियों पर मामला दर्ज करना चाहिए और उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए।*
3. *शासन में भ्रष्टाचार के मामलों से ईमानदार अधिकारियों की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है।*

संविधान पीठ ने कहा है कि शिकायतकर्ता के प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2), धारा 7 और धारा 13 (1)(डी)के तहत लोक सेवक के अपराध का निष्कर्ष निकालने की अनुमति है।

घर खरीददारों के हक में महत्वपूर्ण फैसला

देशभर में लाखों लोग बिल्डरों की लेटलतीफी और बदनीयती के कारण घर खरीदने के लिए पैसा जमा कराने के बावजूद घर का कब्जा पाने के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने घर खरीददारों के हक में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि लोग सपनों के साथ घर खरीदते हैं, उन्हें घर के लिए अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। बिल्डर तय समय में कब्जा नहीं दे पाता है तो उसे खरीददारों को मुआवजा देना होगा।

आयोग ने बेंगलूरु के एनडी डेवलपर्स द्वारा खरीददारों को समय पर घर का कब्जा नहीं दिए जाने को सेवा में कमी माना है और खरीददारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। फैसले में कहा गया है कि कब्जा देने में देरी पर बिल्डर को कुल रकम का उतना फीसदी मुआवजा देना होगा जितना भुगतान में देरी होने पर उपभोक्ता से ब्याज के रूप में वसूलते हैं। आयोग ने 9 फीसदी सालाना ब्याज के साथ जमा कराई गई कुल राशि भी दो महीने के अंदर लौटाने का आदेश दिया है। यदि राशि दो माह में नहीं लौटाई तो पूरी रकम पर सालाना 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2022

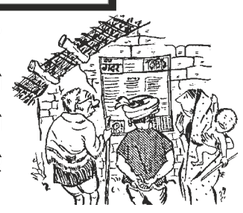

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 41 वर्ष पूरे कर रहा है। अत: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ट पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2022 का विषय जिस पर उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही है, वह है:

'राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं कितनी लाभकारी?'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2022 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

<u>प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2023 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।</u>

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 (राजस्थान), फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org

बायो गैस प्लांट से बन रही जैविक खाद

कोटा में पशुपालकों के लिए बनाई गई विशेष देव नारायण योजना के तहत बने देश के सबसे बड़े बायो गैस प्लांट में जैविक खाद का उत्पादन शुरू हो चुका है। यह खाद डीएपी का जैविक विकल्प बनेगी। इस प्लांट से पूरे हाड़ौती क्षेत्र की डीएपी की जरूरत को जैविक खाद से पूरा किया जा सकेगा।

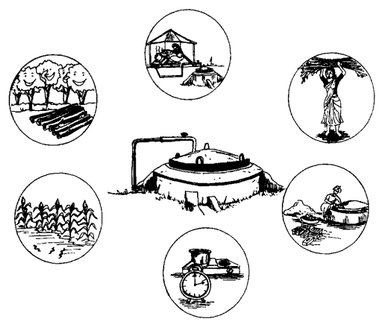

इसके अलावा जैविक तरल खाद से सरकारी उद्यान एवं सार्वजनिक हरियाली वाले क्षेत्रों को पोषण मिल सकेगा। यह प्लांट जैविक खाद फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाएगा। इसके अलावा 17 आवश्यक तत्वों वाला जैविक तरल खाद भी बनाएगा।

इस योजना के तहत 1200 पशुपालक परिवारों के 5 हजार सदस्य होंगे। उनसे एक रुपए किलो के भाव से गोबर खरीदा जा रहा है। जिससे रोजाना 21 टन फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एक लाख लीटर जैविक तरल खाद तथा तीन हजार लीटर कम्प्रेस्ड बायो गैस बनाने की क्षमता है।

अपात्रों ने उठा ली वृद्धावस्था पेंशन

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पिछले तीन साल में कई लोगों ने ई-मित्र के जरिए उम्र बढ़ाकर, आय छुपाकर और परिजन के सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन ले ली। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा दौसा और करौली जिले में हुआ है। यहां करीब 25 हजार लोग जनाधार कार्ड में उम्र को बदलवा कर बुजुर्ग बन गए और पेंशन लेना शुरू कर दिया।

इसकी जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पड़ताल में सामने आई है। विभाग अब उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। दौसा में 14200 और करौली में 10904 मामले सामने आ चुके है।

अन्य कई जिलों में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश में करीब 94 लाख लोग हर माह वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं जिस पर करीब 8800 करोड़ रुपए केंद्र व राज्य सरकार खर्च कर रही है।

हर ग्राम पंचायत में होगा अस्पताल

राजस्थान में ग्रामीण स्तर तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस वर्ष राज्य के सभी जिलों की 11307 ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएंगे। इसके लिए पहली बार ऐसी ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया जा रहा जिनमें आज तक कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है।

सरकार की मंशा है कि 2023 के अंत तक एक भी पंचायत ऐसी नहीं रहे, जिसमें अस्पताल नहीं हो। इस पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं के बजट को बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए सालाना कर दिया है। अभी प्रदेश में 11 हजार उप स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, सीएचसी उप जिला और जिला अस्पताल हैं। इनकी संख्या करीब 17 हजार की जानी है।

प्रदेश में महिला किसान उपजा रही अन्न

राजस्थान में पुरुषों से ज्यादा महिला किसान अन्न उपजाकर देश दुनिया का पेट भर रही है। ई-श्रम पोर्टल 2022 के अनुसार राज्य में कुल 1.25 करोड़ किसान है। इनमें 51.01 फीसदी महिलाएं और 48.99 फीसदी पुरुष किसान हैं। खास बात यह है कि अब प्रदेश की महिला किसान अंगूठा छाप नहीं बल्कि उच्च शिक्षा लेकर खेती में नवाचार कर रही हैं।

कई महिलाएं खेती में नई तकनीक अपनाकर कम पानी में भी अच्छी पैदावार ले रही हैं। यही नहीं, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हो रही हैं। तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब महिला किसानों से जैविक उत्पाद सीधे खेतों से खरीद कर दिल्ली, मुंबई व गुरुग्राम के बड़े स्टोर व पांच सितारा होटलों में बेच रही हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ इच्छाशक्ति दिखाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को राजनीतिक एवं सामाजिक संरक्षण नहीं दिए जाने का आह्वान करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के लंबित मामलों के आधार पर सरकारी विभागों की रेंकिंग की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो इच्छाशक्ति दिखा रही है, वैसी ही इच्छाशक्ति सभी विभागों में भी दिखाई देनी चाहिए।

मोदी ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए विश्वास और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। पहले सरकारों ने न सिर्फ विश्वास खोया, बल्कि लोगों पर भरोसा करने में भी विफल रहीं। हम सरकारी सेवाओं की 'कमी और दबाव' की व्यवस्था को बदलने की कोशिश में हैं।

सरकार चुनने में महिलाओं की हिस्सेदारी

लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा, देश में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। वर्ष 1971 से अब तक महिला मतदाताओं की संख्या में 235.72 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में, पहली बार मतदान करने वाली महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से आगे निकल गया।

महिलाओं ने राजस्थान में भी अपनी निर्णायक भूमिका निभाई। राजस्थान में 2018 के चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74.67 था, वहीं पुरुषों का मतदान प्रतिशत 73.49 रहा। माना जा रहा है कि शिक्षा का बढ़ता स्तर व राजनीतिक जागरूकता इसकी मुख्य वजह है। देश की आधी आबादी की ओर से लगातार चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाना लोकतंत्र के लिए एक सुखद संकेत है।

राष्ट्रपति ने आदिवासियों से जाने हाल

राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयी और उन्होंने राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण किया।

आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि हर देशवासी को संवैधानिक और नैतिक रूप से जागृत होना चाहिए। संविधान में समानता के अधिकार पर जोर दिया गया है।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि कोई भी लोकतंत्र तभी जीवंत कहलाता है जब उसके नागरिक शासन में भाग लेने और देश हित में जिम्मेदारियां संभालने को तत्पर हों।

राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से भी मिली और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने कम उम्र में बच्चों के विवाह नहीं करने तथा महिला शिक्षा पर ध्यान देने को कहा। राष्ट्रपति सहरिया व कथौड़ी आदिवासी समुदाय की महिलाओं से भी मिली और उनके लिए बनी योजनाओं के बारे में पूछा। राष्ट्रपति ने कहा कि योजनाओं का पूरा फायदा उठाएं और आत्मनिर्भर बनें।

किसानों को व्यापार के अवसर दिला रहे है कृषक उत्पादक संगठन

चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) कृषि व्यापार में मदद कर रहे हैं। किसानों के व्यापार को बढाने के लिए 'कट्स' द्वारा संचालित एफ.पी.ओ. प्रोग्राम के माध्यम से हाल ही में मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सी.ई.ओ.) की क्षमतावर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही, निदेशक मंडल के सदस्यों को भी व्यापार की संभावनाओं से अवगत कराया गया।

खाद, बीज एवं दवाइयों की लागत कम हो तथा उपज का उचित मूल्य किसानों को दिलाने के लिए एफ.पी.ओ. के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की बैठक व्यापारियों के साथ चित्तौड़गढ जिले में करवाई गई। इस बैठक के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी व्यापार के गुर सिखते हुए एक कड़ी के रूप में किसानों के व्यापार को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर